(iii) मुआवजे पर और/अथवा रोजगार देने के मामले में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार त्वरित निर्णय ।

कोयला परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब

1770. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं को 6 माह के भीतर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सिद्धान्त के बावजूद इन्हें स्वीकृति देने में 6 माह से अधिक समय लग गया है, यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना के मामले में स्वीकृति देने में लगे समय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को छः माह के भीतर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) नई परियोजनाएं जोकि 50 करोड़ रु० से ऊपर की है उनकी समीक्षा और मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया में निम्न शामिल है–प्रारंभ में मंत्रालय द्वारा गहन मूल्यांकन, सरकार ने विभिन्न अन्य अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन, अन्तर मंत्रालयीय दल और सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार और इसके बाद सक्षम प्राधिकारी से निवेश निर्णयों हेतु स्वीकृति प्राप्त करना अन्तर्निहित है सभी कोणों से एक विस्तृत मूल्यांकन विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि एक बार परियोजना सवीकृत होने पर वूमि, वन भूमि और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की कीमतों से इसके कार्यान्वयन में देरी नहीं होगी । इस प्रकार कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है । किन्तु जहां कहीं सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा पूर्व में ही सिफारिश कोई परियोजना, जिसमें सरकार को प्रस्तुत किए जाने में विलंब होता है; उसमें सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अध्यक्ष की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।

वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान सरकार ने 11 नई कोयला परियोजनाएं स्वीकृत की है, जिसमें अंतिम स्वीकृति के लिए 2 से 5 वर्षों की सीमा तक समयावधि लगी है किन्तु इन 11 कोयला परियोजनाओं में से 9 में अग्रिम कार्रवाई योजना प्रायमिक क्रियाकलाप जैसे भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण कार्य, इत्यादि को शुरू करने के लिए स्वीकृत कर दी गई हैं । एक बार अग्रिम कार्रवाई की स्वीकृत हो जाने पर परियोजना की स्वीकृति एक सामरिक मद के रूप में नहीं रह जाती है चूंकि स्थल पर पूर्व में ही विभिन्न गतिविधियों––जैसे भूमि अधिग्रहण, वन भूमि, पर्यावरणीय स्वीकृति इत्यादि पर कार्रवाई पहले ही शुरू हो जाती है। कोयला परियोजनाओं को आठवीं योजना के समग्र स्रोतों के भीतर त्वरित स्वीकृति हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

investment in Coal Industry

1771. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 15,966 crores have been invested in the coal industry upto 1991-92 since nationalisation;

(b) what was the targeted production after the above mentioned investment in terms of quality and quantity; and

(c) what is the actual production achieved in terms of quality and quantity so far?